Launch and Expansion of QR/UPI Code Based Payment System at M-PACS in Uttar Pradesh

On the occasion of International Year of Cooperatives 2025

A landmark initiative transforming rural cooperatives through digital payments, empowering farmers with cashless, transparent, and secure transactions across Uttar Pradesh.

Prime Minister's Vision and Union Leadership

The launch of QR/UPI Code based payment system at M-PACS in Uttar Pradesh is a landmark initiative in line with the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of "Sahkar se Samriddhi"

This reform has been undertaken under the dynamic leadership of the Hon'ble Union Minister of Cooperation, Shri Amit Shah, who has consistently guided the transformation of M-PACS into multi-purpose, modern, and technology-driven cooperative institutions, serving as the backbone of rural prosperity and inclusive growth.

International Year of Cooperatives

Cooperatives Build a Better World

Inaugural Event

Date & Dignitary

On 23rd August 2025, the Hon'ble Minister of State for Cooperation, Uttar Pradesh (Independent Charge), Shri J.P.S. Rathore, inaugurated the QR/UPI Code based digital payment system at the Cooperative Bank Headquarters, Lucknow.

Significance

The initiative was launched as part of the International Year of Cooperatives 2025 celebrations, aiming to digitize rural cooperatives and empower farmers with cashless, transparent, and secure transactions.

Technology Integration at M-PACS

- Farmers can now make payments for Urea, DAP, seeds, pesticides, and other agricultural inputs using QR/UPI Scan & Pay.
- M-PACS are being equipped with **computers, printers,** LED displays, and solar energy systems, strengthening their role as multi-purpose rural hubs.
- The system eliminates overcharging beyond MRP and ensures accountability, transparency, and convenience.

International Year of Cooperatives

Cooperatives Build a Better World

Expansion Across Districts

The system, launched at Lucknow, is being extended across districts:

Shahjahanpur

Over 100 M-PACS have been issued QR Codes.

Gorakhpur & Eastern UP

Farmers have begun paying digitally, ensuring fair pricing and curbing blackmarketing.

Hapur

After technical upgradation, 36 M-PACS will implement QR/UPI payments this month.

Other Districts

Bareilly, Etawah, Azamgarh, etc.: Rollout is ongoing, ensuring state-wide adoption of digital payments in cooperatives.

International Year of Cooperatives

Cooperatives Build a Better World

Key Highlights from Honorable Minister's Address

6800+

Functional M-PACS

Operating across Uttar Pradesh

10.40 lakh MT

Urea Distribution

Through M-PACS this year, compared to 7.42 lakh MT last year

₹15 lakh

Credit Limit

Raised from ₹10 lakh,
empowering M-PACS financially

Modernization programs include godown renovation, solarization, and equipment support.

International Year of Cooperatives

Cooperatives Build a Better World

Presence of Senior Officials

The successful launch and ongoing district-level expansion of the QR/UPI payment system were strongly supported by the active involvement of key senior officials:

- **Shri Saurabh Babu, Principal Secretary (Cooperation):** Provided strategic direction and policy guidance, ensuring the initiative aligned with the state's broader cooperative development goals.
- **Shri Yogesh Kumar, IAS, Commissioner & Registrar, Cooperation, Uttar Pradesh:** Overseeing the operational rollout and emphasizing the practical benefits for farmers and M-PACS.
- **Alongside other senior officers of the Cooperative Department and Cooperative Bank:** Their collective dedication and coordination were instrumental in the project's rapid implementation.

Their unwavering presence at the inaugural ceremony and during subsequent rollouts across districts powerfully reaffirmed the department's profound commitment to implementing these digital reforms with unparalleled speed, absolute transparency, and unwavering **accountability**, thereby directly benefiting farmers through genuine modernization and empowerment.

Media Report at State Level

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

कृषि ऋण समितियों पर खाद-बीज का भुगतान क्यूआर कोड से अब कर सकेंगे किसान

सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर शनिवार को कोआपरेटिव बैंक मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सचिवों को क्यू-आर कोड प्रदान करते ● सूचना विभाग

राज्य, जागरण● लखनऊ: ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय बहुद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों (एम-पैक्स) में अब क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। शनिवार को सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने उप्र कोआपरेटिव बैंक मुख्यालय में एम-पैक्स क्यूआर कोड प्रणाली का शुभारंभ किया। क्यूआर कोड व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ पैक्स से जुड़े किसानों को होगा। वे खाद, बीज, कीटनाशक तथा अन्य वस्तुएं खरीदने के बाद एम-पैक्स को उनके मूल्य का भुगतान क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकेंगे।

सहकारिता मंत्री ने प्रदेश में सक्रिय 6800 पैक्स में तत्काल क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान शुरू कराने के निर्देश दिए। इन पैक्स के माध्यम से इस समय यूरिया का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर सहकारिता मंत्री ने पांच पैक्स के सचिवों को क्यूआर कोड प्रदान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में यूरिया की कोई कमी नहीं है। यह भी स्वीकार किया कि कुछ समितियों में कार्मिकों की कमी है जिसकी वजह से समितियों को एक-एक दिन के अंतराल पर खोला जा रहा है। मंडल व जिले के अन्य कार्मिकों को समितियों पर तैनात कर किसानों की मांग के मुताबिक उर्वरक का वितरण कराया जा रहा है।

नई व्यवस्था सहकारिता मंत्री ने किया शुभारंभ, कहा- ऑनलाइन भुगतान होने से ज्यादा मूल्य नहीं ले सकेंगे सचिव

अब क्यूआर कोड से भी खाद का भुगतान कर सकेंगे किसान

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों में किसानों को अब क्यूआर कोड से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा मिल सकेगी। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने शनिवार को बाराबंकी के बी-पैक्स उस्मानपुर, इब्राहिमाबाद और लखनऊ की बी-पैक्स रुदान खेड़ा, अनौरा कला, नगराम दक्षिण के सचिवों को क्यूआर कोड उपलब्ध कराते हुए नई व्यवस्था की शुरुआत की।

राठौर ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक एवं डिजिटल स्वरूप देने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। एमपैक्स में क्यूआर कोड आधारित भुगतान प्रणाली लागू होने से ग्रामीण सहकारिता तंत्र को डिजिटल स्वरूप मिलेगा। इससे लेनदेन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुगम होगी। ऑनलाइन भुगतान से निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खरीद-बिक्री के मामले कम होंगे। खाद वितरण व्यवस्था और पारदर्शी होगी। इस मौके पर विभाग के प्रमुख सचिव सौरभ बाबू, आयुक्त योगेश कुमार आदि मौजूद रहे।

नई व्यवस्था के बारे में जानकारी देते सहकारिता राज्यमंत्री जेपीएस राठौर।

समितियों का किया जा रहा आधुनिकीकरण

सहकारिता मंत्री ने बताया कि समितियों में आधुनिकीकरण के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, एलईडी और जहां बिजली उपलब्ध नहीं है वहां 2 किलोवॉट सोलर रूफटॉप पैनल लगवाए जा रहे हैं। समितियों की कार्यशील पूंजी को सुदृढ़ किया गया है। कैश क्रेडिट लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया जाएगा।

सभी जिलों में है पर्याप्त यूरिया

राठौर ने कहा कि सभी जिलों में यूरिया और डीएपी की भरपूर उपलब्धता है। समितियों में यूरिया 266.50 रुपये प्रति बोरी और डीएपी 1350 रुपये बोरी बिक रही है। इस वर्ष सहकारी समितियों से 10.40 लाख मीट्रिक टन यूरिया का वितरण हुआ है। गत वर्ष इसी अवधि में 7.42 लाख मीट्रिक टन वितरण हुआ था। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस समय 6861 प्राथमिक सहकारी समितियां उर्वरक वितरण का कार्य कर रही हैं। पहले सिर्फ 1400 समितियां सक्रिय थीं।

समितियों में क्यूआर कोड से होगा भुगतान

लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों में अब क्यूआर कोड से ऑनलाइन भुगतान हो सकेगा। शनिवार को सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने योजना की शुरुआत की। बाराबंकी के बी-पैक्स उस्मानपुर, इब्राहीमाबाद और लखनऊ की बी-पैक्स रूदान खेड़ा, अनौरा कला, नगराम दक्षिण के सचिवों को क्यू-आर दिए गए। उन्होंने बताया कि सभी प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों को क्यूआर कोड जारी किए जा चुके हैं।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि एमपैक्स में क्यू-आर कोड आधारित भुगतान प्रणाली लागू होने से ग्रामीण सहकारिता तंत्र को डिजिटल स्वरूप मिलेगा। किसानों को नकद लेनदेन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इससे लेनदेन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, होगी। लंबे समय से किसान इस सुविधा की मांग कर रहे थे। अब ऑनलाइन भुगतान की सुविधा से निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खरीद बेचने के मामले में भी कमी आएगी। मौके पर विभाग के प्रमुख सचिव सौरभ बाबू, आयुक्त योगेश कुमार आदि मौजूद रहे।

सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने शनिवार को क्यूआर कोड प्रणाली से भुगतान की शुरुआत की।

प्रदेश में पर्याप्त खाद: सहकारिता मंत्री ने कहा कि सभी जिलों में यूरिया और डीएपी की भरपूर उपलब्धता है। इस वर्ष सहकारी समितियों से 10.40 लाख मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया गया है, जबकि बीते साल इसी अवधि में 7 .42 लाख मीट्रिक टन वितरित हुआ था।

Media Report at District Level

बैठक | **किसानों को नकदी निकालने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे बैंक-जनसेवा केंद्र के चक्कर**

बी-पैक्स को मिले यूपीआई क्यूआर कोड

शाहजहांपुर, संवाददाता। जिला सहकारी बैंक मुख्यालय स्थित मोदी सभागार में शुक्रवार को विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में बैंक अध्यक्ष डीपीएस राठौर ने कहा कि बी पैक्स समितियों के व्यवसाय को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के प्रयास के तहत 100 फीसदी पैक्स को यूपीआई क्यूआर कोड उपलब्ध कराए गए हैं। इससे किसानों को उर्वरक, बीज आदि खरीदने और लोन की ईएमआई जमा करने के लिए अब बैंक या जनसेवा केंद्र के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से ओवर रेटिंग की शिकायतें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। साथ ही, किसानों को सुविधाजनक और पारदर्शी तरीके से सेवाएं मिलेंगी। राठौर ने कहा कि सहकारिता बैंक के नेतृत्व में जिले की प्रगति हो रही है और यह पहल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के डिजिटल इकॉनमी बढ़ाने के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है।

सहकारी समिति में कार्यक्रम के दौरान।

कार्यक्रम में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अखिलेश प्रताप सिंह ने निर्देश दिए कि नयी गठित समितियों के व्यवसाय एक अक्टूबर से शुरू करने की रणनीति तैयार की जाए। बैठक के दौरान बैंक अध्यक्ष राठौर ने उर्वरक वितरण, ऋण वितरण, वसूली और अन्य व्यवसाय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सचिवों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर डीसीवी सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सौरभ द्विवेदी, उप महाप्रबंधक शकील अहमद व राजेश कुशवाहा, अपर जिला सहकारी अधिकारी हरीकेश परमार, एडीसीओ आनंद श्रीवास्तव, संजय सिंह, दिनेश कुमार, शिव रतन लाल, ओमप्रकाश मौर्य, राकेश सिंह, ओमवीर सिंह, अमित मिश्रा, सर्वेश यादव, राजीव सिंह और अतीक्षा सक्सेना मौजूद रहे।

हिन्दुस्तान

सहकारी समितियों पर भी क्यूआर कोड से होगा यूरिया का भुगतान

सुविधा

हापुड़। उर्वरक की बिक्री में पारदर्शिता लाने के लिए सहकारी समितियों में क्यूआर कोड व्यवस्था 2021 में लागू की गई थी परंतु वह फेल हो गई थी। समितियों का बैंक खाता जिला सहकारी बैंक में है, लेकिन वहां नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं थी। जिस कारण समितियों को क्यूआर कोड नहीं मिल पा रहे थे, जबकि शासन ने सरकारी व निजी सभी दुकानों पर क्यूआर कोड लेकर ऑनलाइन उर्वरक की बिक्री करने की अनिवार्यता की थी।

अब 36 समितियों में लागू होगा क्यूआर कोड

अब अपडेट होने के बाद जिले की 36 समितियों पर एक महीने में क्यूआर कोड लागू हो जाएंगे। जिसके बाद किसान मोबाइल से यूरिया का भुगतान कर सकेगा। चार साल पहले शासन ने डिजीटल भुगतान को बढ़ावा देने और उर्वरक केंद्रों पर क्रय-विक्रय में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी उर्वरक बिक्री केंद्रों पर क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटली भुगतान की सेवा को अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद कृषि विभाग ने जिले में संचालित करीब सभी उर्वरक केंद्रों को क्यूआर कोड सेवा शुरू करने के निर्देश दिए थे।

हापुड़ रेलवे गोदाम पर आए यूरिया का निरीक्षण करते एआर एवं प्रशासनिक अधिकारी।

इस माह से शुरू होगी क्यूआर कोड सुविधा

एआर कॉपरेटिव प्रेम शंकर ने बताया कि क्यूआर कोड सेवा शुरू की जा रही है। पूर्व में जिला सहकारी बैंक में डिजिटलकरण न होने के कारण समितियों पर क्यूआर कोड सेवा चालू नहीं हो पाई थी। परंतु अब प्रदेश के सभी जिलों की समितियों में यूपीआई से किसान अपने खाद, यूरिया, डीएपी का भुगतान कर सकेगा। जिले की 36 सहकारी समितियों के लिए क्यूआर कोड उपलब्ध हो चुके हैं। जिला सहकारी बैंक की मशीन आने वाली है। तुरंत डिजिटल भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। किसान को खुले पैसे ले जाकर यूरिया, डीएपी का भुगतान करना पड़ रहा है। जिसमें यूरिया के रेट266 .50 रुपये है। परंतु 50 पैसे को लेकर किसानों से उलझन रहती है। यूपीआई के भुगतान से किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी और मोबाइल से ही भुगतान कर सकेगा।

सुविधा शुरू होने में आ रही थी समस्या

इस प्रक्रिया में सहकारी समितियों के उर्वरक बिक्री केंद्रों पर क्यूआर कोड सेवा शुरू करना संभव नहीं हो पा रहा था। क्योंकि सभी सहकारी समितियों के बैंक खाते जिला सहकारी सहकारी बैंक में हैं और जिला सहकारी बैंक के पास यूपीआई लाइव की सुविधा नहीं थी। जिस कारण सहकारी समितियों के उर्वरक बिक्री केंद्रों पर क्यूआर कोड सुविधा शुरू नहीं हो पा रही थी। परंतु अब सहकारी समितियों को अपडेट कर दिया गया है। सहकारी समितियों को किसानों के उद्योग की तरह काम किया जाएगा।

Media Report at District Level

हिन्दुस्तान

कैश को लेकर दिक्कत के मद्देनजर डिजिटल लेनदेन की सुविधा बढ़ी, एचयूआरएल की 614 टन यूरिया मिली

किसान यूपीआई से करें यूरिया मूल्य का भुगतान, मनमाने दाम पर लगेगा अंकुश

सुविधा

गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। किसानों को उर्वरक वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। अब किसानों को यूरिया के लिए कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहकारी समितियों पर प्रदर्शित क्यूआर कोड की मदद से किसान यूपीआई के माध्यम से यूरिया के 45 किलोग्राम के बैग की निर्धारित कीमत 266.50 रुपये का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इससे जहां ओवर रेटिंग पर लगाम लगेगी, वहीं किसानों को भी डिजिटल लेन-देन की सुविधा मिलेगी।

एआर कोऑपरेटिव गोरखपुर, नीरज कुमार ने बताया कि जिले की सभी सहकारी समितियों को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए क्यूआर कोड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक 110 समितियों को यह सुविधा दी जा चुकी है। किसान इन क्यूआर कोड्स के माध्यम से यूपीआई से भुगतान कर यूरिया प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसान एक यूरिया बैग की कीमत 266.50 रुपये है। इस कदम से ओवर रेटिंग पर प्रभावी नियंत्रण होगा।

साधन सहकारी समिति नथुआ पर क्यू आरकोड से यूरिया खाद की कीमत का भुगतान करते किसान (बाएं)। नकहा रैप पर आई निजी यूरिया की खेप,समितियों पर सीधे भेजी जा रही।

1300 टन यूरिया मिली, रैक से सीधे समितियों को भेजा

बुधवार को निजी उर्वरक कंपनी आईपीएल की यूरिया रैक गोरखपुर के रेल हेड नकहा जंगल में प्राप्त हुई। शासनदेश के अनुरूप 50 प्रतिशत यानी 686 टन यूरिया सहकारिता विभाग को आवंटित की गई, जिसका प्रेषण सीधे 41 समितियों को भेजा गया। वहीं, गुरुवार को एक अन्य निजी उर्वरक कम्पनी एचयूआरएल की रैक प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से 614 टन यूरिया 32 समितियों को आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त पीसीएफ बफर गोदाम में लगभग 796 टन यूरिया संरक्षित है, जिसे समितियों की मांग के अनुसार लगातार भेजा जा रहा है।

करमैनी में अधिक दाम पर बेची जा रही यूरिया

कैंपियरगंज, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के करमैनीघाट में यूरिया खाद की ओवररेटिंग का मामला सामने आया है। दुकानदार सरकारी दर 266 रुपये प्रति बोरे की जगह 400 से 560 रुपये में खाद बेच रहे हैं।

दुकानदार स्टॉक न होने का बहाना बनाकर सरकारी दर पर खाद देने से मना कर देते हैं। इससे गरीब और छोटे किसानों को मजबूरी में महंगी खाद खरीदनी पड़ रही है। खरीफ की फसल के महत्वपूर्ण समय में खाद की कमी से किसान परेशान हैं। किसान जगदीश, बिन्दू, सुग्रीम, रविंद्र, बजरंगी, बदरी आदि ने प्रशासन से कार्रवाई के लिए गुहार लगाई है।

जल्द खत्म होगी ओवररेटिंग, 115 पैक्स को जारी किए क्यूआर कोड

डीसीबी अध्यक्ष डीपीएस राठौर ने पैक्स सचिवों को किया सम्मानित

कहां गुम है खाद

जांस, शाहजहांपुर : जिला सहकारी बैंक मुख्यालय पर शुक्रवार को समीक्षा बैठक हुई। इसमें प्रत्येक समिति पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। 115 पैक्स को क्यूआर कोड जारी कर दिए गए, जिससे ओवररेटिंग की शिकायतें कम होंगी। इस बीच उत्कृष्ट कार्य के लिए पैक्स सचिवों को सम्मानित किया गया।

बैंक अध्यक्ष डीपीएस राठौर ने कहा कि बी पैक्स (समितियों) के व्यवसाय को आधुनिक बनाने के प्रयास के तहत शत-प्रतिशत पैक्स को यूपीआई क्यूआर कोड उपलब्ध कराए गए हैं। क्यूआर कोड जारी होने से ओवररेटिंग की शिकायतें खत्म हो जाएंगी और किसानों को उर्वरक आदि खरीदने अथवा लोन की ईएमआइ देने के लिए नगदी निकालने के लिए बैंक या जनसेवा केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने उर्वरक वितरण, ऋण वितरण वसूली अन्य व्यवसाय करने वाले सचिवों को सम्मानित किया। इस मौके पर सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अखिलेश प्रताप सिंह, सचिव ,व मुख्य कार्यपालक अधिकारी सौरभ द्विवेदी, उप महाप्रबंधक शकील अहमद, राजेश कुशवाहा, अपर जिला सहकारी अधिकारी बैंकिंग हरीकेश परमार, एडीसीओ आनंद श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

जिला सहकारी बैंक स्थित मोदी सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते चेयरमैन डीपीएस राठौर • सौ. विभाग

International Year of Cooperatives

Cooperatives Build a Better World

Conclusion

Historic Digitalization

QR/UPI Code based digital payment system marks a historic step in cooperative modernization

Farmer-Centric

Makes cooperatives transparent, modern, and focused on rural prosperity

Aligned with Vision

Supports Prime Minister's vision of "Sahkar se Samriddhi" and farmer prosperity

Strong Leadership

Highlights Union Minister of Cooperation's guidance in transforming M-PACS